

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १ जुलाई, 2015

विषय:- जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत जिला कारागार की स्थापना हेतु ग्राम गडरियाबाग तहसील किच्छा खाता संख्या-2 के खसरा संख्या-91 मि० रकबा 4.050 है० भूमि गृह (कारागार) विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-07/सात-स०भू०आ०/2014 दिनांक 4-10-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद उधमसिंहनगर के ग्राम गडरियाबाग तहसील किच्छा खाता संख्या-2 के खसरा संख्या-91 मि० रकबा 4.050 है०, श्रेणी-5 नवीन परती भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-2-2002 एवं संख्या-111/XXVII(7)50(39)-2015/2014 दिनांक 9-7-2015 में निहित प्राविधानों के अधीन गृह (कारागार) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय प्रस्ताव/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जिला कारागार की स्थापना हेतु गृह (कारागार) विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

Alex



8. प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011/SLC/ No 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दिनांक जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
  11. उपरोक्तानुसार किया गया भूमि हस्तान्तरण रिट याचिका संख्या-1001/2005 पवन पापुलर लि0 बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं याचिका संख्या-1002/2005 प्राग एग्रो फार्म लि0 बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।


भवदीय

(जे0पी0 जोशी)  
अपर सचिव

पू0सं0-1446 / XVIII (II) 2015-18(121) / 2015, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, कारागार विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(आलोक कुमार सिंह)  
अनु सचिव